सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

सफलता की कुंजी

यदि कोई देश भ्रष्टाचार मुक्त और अच्छे मस्तिष्क वाला देश बनता है, तो ऐसा होने के लिए केवल तीन ही सामाजिक सदस्य बदलाव ला सकते है और वे तीन सदस्य पिता, माता और शिक्षक है।
– डा. अब्दुल कलाम

अनमोल विचार

संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है। असंभव से भी आगे निकल जाना।
-स्वामी विवेकानंद

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-1 • 11 DECEMBER TO 17 DECEMBER 2019 • VOLUME-17 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

राईट कट लैफ्ट कट ये सब भ्रष्ट अफसरों द्वारा बनाये हुए शॉट कट

हाईकोर्ट के नियमों की उल्लंघना करते हुए अवैध तरीके से कट खोल कर परपेंडिकुलर एक्सिस को भ्रष्ट अफसरों द्वारा मौत के मुंह में लोगों को धकेला जा रहा है

नैशनल हाईवे विभाग

मशहूर ढाबे को जाने के लिए स्पैशल कट।

सूर्या एन्कलेव का कट।

गुरुगोबिंद एवेन्यू का कट

इंडियन ऑयल वाला कट

दकोहा फाटक वाला कट

कैंट वाला कट

सरब मल्टीप्लेक्स वाला कट

कालिया कालोनी वाला कट

■ जालंधर से विजय कुमार की विशेष रिपोर्ट

अमृतसर पानीपत हाईवे जो कि जालंधर ब्रीज द्वारा कई अंकों में इसको खूनी हाईवे के नाम से भी पुकारा जाता है। यह जालंधर ब्रीज द्वारा कोई मनगढ़त रूप से नहीं इसको नाम दिया गया इसका कारण इस हाईवे पर भ्रष्ट अफसरों द्वारा की गई त्रुटीयों जिनको उजागर कई बार किया गया परन्तु विभाग के भ्रष्ट अफसर इतने भ्रष्ट हो चुके है कि यह सिर्फ किसी भी कदम को खानापूर्ति के रूप में उठाते है फिर उसको उसी हालात में छोड़ देते है उदाहरण स्वरूप नैशनल हाईवे विभाग द्वारा किए गए अवैध कट कहीं से बंद कर दिये गये और विधायकों की धमकी के बाद उसे खोल दिया गया है। लगता है नैशनल हाईवे विभाग इन नियमों को लागू ही नहीं करना चाहता है और शायद इन भ्रष्ट अफसरों का जब तक इनका कोई अपना इस दुनिया से अलविदा नहीं कहेगा उस से पहले इनको किसी कानून को समझने की जरूरत नहीं है हाल ही में भगत सिंह कालोनी के बाहर बंद किये गये कट और सरब मल्टीपलैक्स से पहले खोले गये कट और सूर्य इन्कलेव जाने के लिए कट पर जिस प्रकार की छोटी सी साईनेज करके लोगों को रास्ता समझाया गया।

शायद यह सिर्फ इनको ही पता लगे और किसी को पता ना लगे और जिस प्रकार से कट के लिए मेन कैरिजवे से ट्रैफिक को स्लिप रोड का निर्माण किया जाना चाहिए इसको छोटा सा कट खोल कर लोगों को हादसों का शिकार होने के लिए बुलावा देने के समान है अगर किसी प्राईवेट ढाबा जोकि जी.टी. रोड पर स्थित है जिसका एक जज द्वारा रोड़ पर किये अवैध कब्जे भी हटवाये गये थे उसके लिए कट की प्रोविज़न रोड बना कर दी गई है उसके मशहूर ढाबे के सामने जो पिछली सरकार द्वारा फ्लाई ओवर बना कर पंजाब के प्रमुख नेता द्वारा नुकसान किया गया था उसकी भरपाई बढ़िया रोड कनैक्टीविटी देकर की गई है क्योंकि वो भी भ्रष्ट अफसरों को पालने के शौकीन है और अपनी मर्जी से लैफ्ट कट राईट कट अपने द्वारा बनाए हुए शार्ट कट के माहिर है।

बिल्डिंग विभाग के भ्रष्ट अफसरों पर देशद्रोही का पर्चा दर्ज करवाये सरकार

■ जालंधर से विजय कुमार की विशेष रिपोर्ट

आज कल संसद में रोज़ाना केन्द्र की सरकार द्वारा नया बिल पेश करके उसको दोनों सभाओं से पास करवा कर कानून का रूप दिया जा रहा है। उसे देश में कानून व्यवस्था और देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए समय की जरूरत भी समझा जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा संसद में या अपनी चुनावी रैलीयों में अक्सर इस बात का हवाला दिया जाता है कि मेरे द्वारा रोज़ाना एक बेफजूल कानून को खत्म करके चीजों को सरल करने का प्रयास किया जा रहा है, परन्तु प्रधानमंत्री को एक चीज की तरफ बखूबी ध्यान देना पड़ेगा कि देश की हर हाईकोर्ट में चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो, महाराष्ट्र हाईकोर्ट हो या पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट हो इसमें रोजाना शहरों में अवैध निर्माणों को लेकर याचिकायें दायर होती रहती है जिससे कि जो काम अफसरों द्वारा किए जाना चाहिए जैसे कि शहर की सुन्दरता और जरूरतों को देखते हुए किसी तरह का भी किसी शहर में अवैध बिल्डिंगों का निर्माण ना हो इसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाने अति अवश्यक होते है परन्तु एक उदाहरण जैसे कि जालंधर के एक आर.टी.आई एक्टीविस्ट द्वारा जालंधर में हो रहे अवैध निर्माणों की भरमार को देखते हुये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई जिसमें उसके द्वारा शहर में बिगड़ रही ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बिल्डिंगों में पार्किंग का ना होना और रिहाईशी इलाकों में कर्मिशयल अदारों का खुलना उसके प्रति चिंता व्यक्त की गई जिसके परिणामस्वरूप चीफ जस्टिस द्वारा इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए अफसरों को इसको गिराने के समयबंद किया गया। क्या अवैध निर्माणों के लिए अफसर जिम्मेवार नहीं जिन्होंने इस चीज को पनपने क्यों दिया और भेदभाव का व्यवहार लोगों से क्यों किया लोगों को यह क्यों महसूस करवाया जा रहा है कि अगर आप ने जालंधर शहर में कोई अवैध निर्माण करना है तो आपको शहर के प्रमुख राजनेताओ, मीडिया घरानो, भ्रष्ट अफसरों के यहां दिवाली दशहरा पर महंगे महंगे उपहार समय पर पहुंचाने होगें। पिछले दिनों पूर्व निकाय मंत्री द्वारा भी अचानक एक शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई जिसमें कि उसने भ्रष्ट अफसरों को तत्काल रूप से ड्यूटी में कोताही बरतने के

लोकल बॉडी विभाग

जुर्म में सस्पैंड किया गया था। परन्तु इन भ्रष्ट अफसरों के पास आज की तारीख में इतना पैसे और पहुंच हो चुकी है कि इन्होंने मंत्री ही बदला दिया और खुद बहाल होकर भ्रष्टाचार को ओर चरम सीमा पर बढ़ावा दे रहे है जिस का एक उदाहरण उस समय का कमिश्नर जो कि आई.ए.एस.अधिकारी था उस पर इस अवैध निर्माणों में भागीदार होने का आरोप लगा था और उस पर पूर्व निकाय मंत्री द्वारा लिखित में मुख्यमंत्री को सिफारिश की गई थी परन्तु वो इतना ताकतवर था कि वो इस राज्य सरकार से एन.ओ.सी. प्राप्त करके केन्द्र मंत्री का पर्सनल सैक्टरी के रूप में दिल्ली कार्यरत है यह सभी तथ्य इन सभी चीजों का प्रमाण है कि एक भोला भाला इंसान हिन्दोस्तान में रोज़ाना किसी ना किसी हाथों से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इन भ्रष्ट अफसरों के जाल में ऐसे फंस गया कि जैसे सांप के मुंह में कोढ़किरली, वो खाये तो भी मरे ना खाये तो भी मरे क्योंकि अवैध निर्माण रातों रात तो नहीं हो गये अगर कोई रिहायशी इलाके में कमर्शियल दुकान अवैध है तो सरकार इसकी राजिस्ट्री पर रोक क्यों नहीं लगाती ताकि कोई प्रापर्टी की गलत खरीद फरोख्त की ना जा सके। इन सभी चीजों के लिए भ्रष्ट अफसर जिम्मेवार हैं क्योंकि इन्होंने देश की तरक्की को सुचारू ढंग से होने में रोका और यह भी देश विरोधी गतिविधि है इसलिए इन भ्रष्ट बिल्डिंग विभाग के अफसरों पर देशद्रोही का पर्चा दर्ज हो अगर इसकी करप्शन एक्ट में प्रोविजन नहीं है तो इसके लिए विधानसभा या लोकसभा में बिल के रूप में लाकर इसको कानून में तबदील करवाये सरकार।

नागरिकता संशोधन बिल : राहुल गांधी बोले- देश की नींव को नष्ट किया जा रहा है

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति के बीच नागरिकता संशोधन बिल (CAB) को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। अब बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इससे पहले आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नागरिकता संशोधन बिल को लेकर कहा है कि इसका समर्थन करना भारत की बुनियाद को नष्ट करने का प्रयास होगा। राहुल गांधी ने कहा, ''नागरिकता संशोधन विधेयक संविधान पर हमला है। जो कोई भी इसका समर्थन करता है वो हमारे देश की बुनियाद पर हमला और इसे नष्ट करने का प्रयास कर रहा है।'' कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सीएबी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी संविधान को

(शेष पृष्ठ 3 पर)

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

IELTS • PTE • TOEFL
SPOKEN ENGLISH

TOURIST VISA | STUDY VISA | PR
WORK PERMIT | HOLIDAY PACKAGES

CANADA AUSTRALIA USA U.K SINGAPORE EUROPE

9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal.
HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.
E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com
Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin

उक्ति

क्रोध करने की आदत गर्म कोयले को किसी दूसरे पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के सामान है। इसमें केवल आप ही जलते हैं। इसीलिए क्रोध का परित्याग शीघ्र करें।

■ महात्मा बुद्ध

www.jalandharbreeze.com

साप्ताहिक
11 दिसंबर से 17 दिसंबर 2019
जालंधर ब्रीज

दखल

आग में खाक होती जिंदगी

सुरक्षा मानकों की अनदेखी का ही नतीजा है कि देश भर में आग की घटनाओं में तेजी आई है और लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ रहा है। अमूमन माना जाता है कि इस तरह की हृदयविदारक घटनाओं से सरकारें सबक लेंगी और आपदा प्रबंधन को चुस्त-दुरुस्त करेंगी। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। शायद सरकारें अग्निजनित हादसों को आपदा मानने को तैयार ही नहीं है। तभी तो अब तक इसे रोकने के इंतजाम नहीं हो पाए हैं।

राजधानी दिल्ली के रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी में लगी भीषण आग में 43 लोगों की दर्दनाक मौत रेखांकित करने के लिए पर्याप्त है कि चाहे सावर्जनिक स्थल हो अथवा शिक्षण संस्थान, फैक्टरी, रेल, वायुयान, चिकित्सालय, निजी संरक्षण गृह, समारोह स्थल, रेस्टोरेंट और आस्था केंद्र कोई भी स्थान आग की लपटों से सुरक्षित नहीं है। हर जगह अग्नि का तांडव देखने को मिल रहा है। अनाज मंडी में लगी आग की भयानकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तीसरी मंजिल पर चल रही पैकेजिंग फैक्ट्री को भी आग की जद में आते देर नहीं लगी। बताया जा रहा है कि संकरी गलियों में स्थित पैकेजिंग और बैग बनाने वाली फैक्ट्री में शार्ट सर्किट होने से आग लगी। जिस समय आग लगी उस समय एक-एक कमरे में 20-20 लोग सो रहे थे। अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। अभी भी डेढ़ दर्जन से अधिक लोग जीवन और मौत के बीच झूल रहे हैं। बहरहाल यह आग कैसे लगी यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आग की घटनाओं से निपटने के लिए तंत्र के पास कोई ठोस और त्वरित उपाय नहीं है।

ऐसा इसलिए कि पिछली दिवाली पर राजधानी दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में एक दुकान समेत 90 से अधिक स्थानों पर आग लगने की घटनाएं हुई। राजधानी दिल्ली में ही पिछले अगस्त में एम्स में भीषण आग लगी थी। अभी गत वर्ष ही बाहरी दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर पांच में एक इमारत में अवैध रूप से चल रही पटाखे की फैक्टरी में भीषण आग में 17 लोगों की जान गई। यह पर्याप्त नहीं कि राज्य सरकारें मृतकों और घायलों के परिजनों को मुआवजा थमाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ले। आग की घटनाओं से निपटने के लिए सरकारों को संवेदनशील होना होगा एवं ठोस उपाए ढूंढने होंगे। लेकिन घोर असंवेदनशीलता का नतीजा है कि देश में आए दिन भीषण आग में लोगों की जान जा रही है। गौर करें तो यह पहली बार नहीं है जब तंत्र की लापरवाही की वजह से आग में जिंदगियां खाक हुई हैं। याद होगा कि गत वर्ष पहले सूरत की तक्षशिला कॉम्पलेक्स की चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग में 23 लोगों की मौत हुई थी।

इसी तरह गत वर्ष पहले मध्य मुंबई के लोअर परेल इलाके में निर्मित दो रेस्टोरेंट कम पब में अचानक भड़की आग में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। दरअसल आग की घटनाओं का मूल कारण यह है कि सार्वजनिक स्थलों व इमारतों में आग से बचाव को लेकर सतर्कता का अभाव है। इसके लिए सर्वाधिक रुप से सरकारी तंत्र के वे भ्रष्ट अधिकारी ही जिम्मेदार हैं जो पैसे लेकर एनओसी जारी कर देते हैं। याद होगा गत वर्ष पहले लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में शार्ट सर्किट से लगी आग में छह मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसी तरह कोलकाता के नामी-गिरामी निजी अस्पताल एडवांस मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में लगी आग में 90 लोगों की जान गई थी। हादसों पर गौर करें तो दिसंबर 1995 में हरियाणा के मंडी डबवाली में स्कूल के एक कार्यक्रम के दौरान पंडाल में आग लगने से तकरीबन 442 बच्चों की मौत हो गई थी। छह जुलाई, 2004 को तमिलनाडु के कुंभकोणम जिले में आग से 91 स्कूली बच्चों ने दम तोड़ दिया था। इस हृदय विदारक घटना के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने आपदा प्रबंधन को चुस्त-दुरुस्त करने का वादा किया। स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फरमान जारी किया गया कि वे अपने यहां अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

दिखावे के तौर पर स्कूलों और कोचिंग संस्थानों ने उपकरणों की व्यवस्था तो कर ली लेकिन वे सिर्फ हाथी दांत ही साबित हो रहे हैं। उसका एक कारण यह भी है कि जिन स्कूलों और संस्थानों में इन अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की गई है वहां उसका इस्तेमाल कैसे हो इसकी भी जानकारी कर्मियों को नहीं है। यहीं वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी इमारतें और निजी अस्पताल भीषण अग्निकांड के शिकार हो रहे हैं। अब तो उत्सव और आयोजन भी आग की भेंट चढ़ रहे हैं। याद होगा गत वर्ष पहले केरल के कोल्लम में पुत्तिंगल देवी मंदिर में आतिशबाजी से लगी आग में एक सैकड़ा से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत हुई। गत वर्ष पहले उज्जैन जिले के बड़नगर में पटाखे की फैक्टरी में भीषण आग में डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों को जान गई। आंध्रप्रदेश के पूर्वी गोदावरी में भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड यानी गेल की गैस पाइपलाइन में लगी आग से हुए विस्फोट में डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों की जान गई। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पर एक इमारत धूं-धूं कर जल उठी, वहीं यूपी के कानपुर में लिकेज सिलेंडर से आग लगने से पांच लोगों की जान चली गयी। गत वर्ष पहले तमिलनाडु के शिवकाशी के मुदालीपट्टी में पटाखे की एक फैक्टरी में आग लगने से 54 लोगों की मौत हुई।

31 मई 1999 को दिल्ली के लालकुआं स्थित हमदर्द दवाखाना में केमिकल से लगी आग में 16 लोगों को जान गई। छह अगस्त, 2001 को तमिलनाडु के इरवदी जिले में स्थित एक निजी संरक्षण गृह में आग लगने से मानसिक रूप से कमजोर 28 लोग जलकर मर गए। तमिलनाडु के ही श्रीरंगम विवाह समारोह में आग लगने से 50 लोग काल-कवलित हुए। 7 दिसंबर 2004 को दिल्ली के भोलानाथ नगर में होजरी फैक्ट्री में आग लगने से एक दर्जन लोग मारे गए। 15 सितंबर, 2005 को बिहार में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 35 लोग जलकर खाक हुए। 10 अप्रैल, 2006 को मेरठ के विक्टोरिया पार्क में लगे मेले में भीषण आग में 60 लोगों की जलकर मौत हुई। गत वर्ष पहले देश की राजधानी दिल्ली में किन्नरों के महासम्मेलन के दौरान पंडाल में लगी आग से 16 किन्नरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। 23 मार्च, 2010 को कोलकाता के स्टीफन कोर्ट बिल्डिंग में लगी आग में 46 लोग और 20 नवंबर 2011 को दिल्ली के नंदनगरी में आयोजित एक समारोह में 14 लोग मारे गए। 27 जुलाई, 2005 को मुंबई के पास बांबे हाई में ओएनजीसी प्लेटफार्म पर आग में 12 लोगों को जान गंवानी पड़ी। जून 2012 में महाराष्ट्र सरकार का मंत्रालय अग्नि की भेंट चढ़ गया।

13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में आग लगने से 59 लोगों की मौत हुई। इस घटना के बाद राज्य सरकारों ने अपने राज्य के सिनेमा हॉल प्रबंधकों को ताकीद किया कि वह सिनेमा हॉलों को अग्निशमन यंत्रों से लैस करें। प्रशिक्षित लोगों की नियुक्ति करें। लेकिन यह सच्चाई है कि आज भी सिनेमा हॉल और मॉल सुरक्षित नहीं हैं। देश में जब भी इस तरह के हादसे होते हैं अक्सर सरकार और जिम्मेदार संस्थाओं द्वारा मुआवजा थमाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लिया जाता है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है कि वह आग से बचाव के लिए रणनीति बनाएं। सुरक्षा मानकों की अनदेखी का ही नतीजा है कि देश भर में आग की घटनाओं में तेजी आई है और लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ रहा है। माना जाता है कि इस तरह की हृदयविदारक घटनाओं से सरकारें सबक लेंगी और आपदा प्रबंधन को चुस्त-दुरुस्त करेंगी। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। शायद सरकारें एवं सार्वजनिक संस्थाएं अग्निजनित हादसों को आपदा मानने को तैयार ही नहीं है। अन्यथा कोई कारण नहीं कि भीषण अग्निकांड के बाद भी शासन-प्रशासन बैठा रहे।

■ अरविंद जयतिलक
(वरिष्ठ पत्रकार)

विचार

कर्नाटक ने दी भाजपा को राहत

महाराष्ट्र में गच्चा खाने के बाद कर्नाटक भाजपा के लिए टॉनिक बनकर आया है। अगर यहां भाजपा को उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिलता तो उसके मनोबल पर असर पड़ता। साथ ही पूरे देश में यह संदेश भी जाता कि भाजपा अब अपराजेय नहीं रही।

महाराष्ट्र में भाजपा को मिले बड़े झटके के बाद कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार ने कुर्सी बचा ली है। राज्य में 15 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने बहुमत के लिए जरूरी छह सीटें बचा ली हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब येदियुरप्पा सरकार अपना कार्यकाल आसानी से पूरा कर लेगी और विपक्ष की सरकार गिराने की हरसत इस कार्यकाल में पूरी नहीं होने वाली। महाराष्ट्र और हाल के पश्चिम बंगाल उपचुनाव के झटके के बाद कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी थीं। झारखंड में बहुकोणीय लड़ाई के बीच कर्नाटक का प्रदर्शन भाजपा के मनोबल पर जरूर प्रभाव डालेगा। अगर भाजपा यहां जरूरत की छह सीटें नहीं जीत पाती तो कर्नाटक में एक बार फिर बवंडर मच सकता था। येदियुरप्पा सरकार को इस्तीफा देना पड़ता और कांग्रेस-जेडीएस के बीच फिर सरकार बनाने की गुंजाइश बनती।

बता दें कि कर्नाटक में उन 15 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं जहां से कांग्रेस और जदएस के बागी विधायकों ने उनकी सरकार गिरा दी थी और सत्ता दूसरी बार भाजपा के हाथ आई है। लेकिन अब तक भाजपा विधानसभा संख्या के अनुसार बहुमत में नहीं थी। आज आए नतीजे ही भाजपा का शक्ति परीक्षण माने जाएंगे। अब तक फिलहाल भाजपा के पास 105 सीटें हैं। कहा जा रहा था कि 15 सीटों पर होने वाले चुनाव के बाद भाजपा को सरकार बचाने के लिए कम से कम सीत सीटें चाहिए होंगी क्योंकि दो अन्य रिक्त सीट पर फिलहाल चुनाव नहीं हुए हैं। लेकिन भाजपा इससे ज्यादा सीटें झोली में झाल चुकी है। भाजपा ने कर्नाटक में बागियों को ही टिकट दिए थे जो अपने क्षेत्रों में मजबूत हैं। कांग्रेस और जदएस इस चुनाव को एक अवसर के रूप में देख रही थीं। खासकर महाराष्ट्र में शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन के बाद जिस तरह जदएस के नेताओं की ओर से बयान आए और यह संकेत दिया गया कि उन्हें भाजपा के साथ आने में परहेज नहीं होगा। जबकि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अब पूरा जोर लगाने का संकेत दिया गया ताकि भाजपा को असहज दिलाया जा सके।

भाजपा के अंदर भी एक धड़ा ऐसा है जो शुरू से जदएस को साथ लेकर चलने की हिमायत करता रहा है। अटकलें ऐसी भी लगाई जाती रही है कि पिछले चुनाव में जदएस को सकारात्मक संदेश देने के लिहाज से कुछ सीटों पर कमजोर उम्मीदवार उतारने की बात हुई, लेकिन नेतृत्व ने इसे नकार दिया। अब कर्नाटक में आए नतीजों का असर झारखंड के चुनाव पर अवश्य रूप से दिखेगा। अब वहां तीन चरणों का मतदान शेष है। महाराष्ट्र में गच्चा खाने के बाद कर्नाटक भाजपा के लिए टॉनिक बनकर आया है। अगर यहां भाजपा को उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिलता तो उसके मनोबल पर असर पड़ता। साथ ही पूरे देश में यह संदेश भी जाता कि भाजपा अब अपराजेय नहीं रही। यह स्थिति विपक्ष को ताकत देती।

इंटरनेट बच्चों के लिए घातक

हैदराबाद रेप कांड के बाद इस बात पर भी चिंता जताई गई थी कि तेजी से बढ़ता पोर्न फिल्मों का चलन युवाओं को अपराध की तरफ ले जा रहा है। एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि स्कूलों में पढ़ने वाले हर पांच छात्र में से एक छात्र इंटरनेट की बुरी लत का शिकार है। इस तरह के सर्वे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक परिस्थिति में जरा भी बदलाव नहीं आया है, लेकिन अब हमें इस दिशा में सोचना होगा।

सूचना तकनीक और इंटरनेट ने इस दुनिया के विकास में बड़ा योगदान दिया है लेकिन अब तेजी से इसके बड़े दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मसलन इंसान तकनीक का गुलाम बनता जा रहा है। बच्चों का बचपन भी अब इंटरनेट की गिरफ्त में आ चुका है या यह कहें कि बच्चे भी अब तेजी से इंटरनेट की गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। बाजार ने बच्चों के लिए भी इंटरनेट पर इतना कुछ दे दिया है कि वह पढ़ने के अलावा अपना ज्यादातर समय इंटरनेट पर ही बिता रहे हैं। पिछले दिनों फ्रांस की संसद ने एक कानून बनाकर देश के प्राथमिक और जूनियर हायर सेकंडरी स्कूलों में बच्चों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। यह कानून वर्तमान स्कूली सत्र यानी सितंबर 2018 से लागू हो गया है। इसके बाद दुनियाभर में इस पर बहस शुरू हो गई है, कई लोग स्कूल में मोबाइल के फायदे गिना रहे हैं जबकि फ्रांस के युवा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने विभिन्न सर्वेक्षण रिपोर्ट को आधार बनाकर ही अपने देश में बच्चों के स्कूल में सेल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल खुद पेश किया और सांसदों से इसके लिए समर्थन मांगा।

फ्रांस जैसे विकसित देश के इस कदम से भारत में भी कुछ लोग ऐसी पाबंदी के कानून की बात कर रहे हैं क्योंकि यहां स्कूलों में मोबाइल फोन के दुरुपयोग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्कूली बच्चों के यौन शोषण से तैयार अश्लील वीडियो क्लिप से इंटरनेट संसार भरा पड़ा है। असल में कम उम्र के बच्चे क्लास में फोन लेकर बोर्ड और पुस्तकों के स्थान पर मोबाइल पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वे एक-दूसरे को मैसेज भेजकर बातें करते है या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर सक्रिय रहते हैं। इससे उनके सीखने और याद रखने की गति तो प्रभावित हो ही रही है, अब स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर हो रहा है। अब वे खेल के मैदान में पसीना बहाने के बजाय आभासी दुनिया में व्यस्त रहते हैं, इससे कम उम्र में ही उनमें मोटापा, आलस्य, आंखें कमजोर होना, याददाश्त कमजोर होने जैसे प्रभाव भी दिखने लगे हैं। पहले बच्चे जिस गिनती, पहाड़े, स्पेलिंग या तथ्य को अपनी स्मृति में रखते थे, अब वे सर्च इंजन की चाहत में उसे याद नहीं रखते, यहां तक की कई बच्चों को अपने घर का फोन नंबर तक याद नहीं रहता। ऐसे में अपने देश के स्कूलों में कम से कम भी आठवीं कक्षा तक मोबाइल प्रतिबंधित होना चाहिए।

अभी पिछले दिनों दिल्ली पुलिस और एम्स के बिहेवियर एडिक्शन यूनिट द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है कि स्कूलों में पढ़ने वाले हर पांच छात्र में से एक छात्र प्रोब्लेमेटिक इंटरनेट यूजर यानी पीआईयू का शिकार है। पीआईयू का अर्थ है कि हर पांच में से एक छात्र इंटरनेट की बुरी लत का शिकार है। इंटरनेट गेमिंग, सर्फिंग या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने इन युवाओं का इंटरनेट का क्रेज इनकी पढ़ाई, सोशल लाइफ व करियर को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। सर्वे के मुताबिक 37 फीसदी छात्र मिजाज और पढ़ाई के प्रेशर से ध्यान हटाने के लिए इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं। इस सर्वे में दिल्ली के साउथ इस्ट डिस्ट्रिक्ट के 25 नामी स्कूलों के कुल 6291 छात्रों ने हिस्सा लिया। इसमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को शामिल किया गया। सर्वे छात्रों के इंटरनेट यूजेस पैटर्न पर आधारित था जिसमें सिकोमेट्रिक स्केल पर 15 अलग-अलग आइटम या केटेगरी में छात्रों के इंटरनेट पर बिताए गए समय व पैटर्न पर उनको रेट किया गया। अगर स्कोर 60 के ऊपर है तो छात्र पीआईयू यानी प्रोब्लेमेटिक इंटरनेट यूजर है।

सर्वे के मुताबिक 19 फीसदी छात्रों के 60 के ऊपर स्कोर मिले जो कि बेहद चिंता का विषय है। जहां एक तरफ ये आंकड़े दूसरे एशियाई देशों के बराबर हैं वही उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों से कहीं ज्यादा है। दिल्ली पुलिस और एम्स की संयुक्त टीम की अगर माने तो दिल्ली में ये आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि 22 फीसदी छात्रों ने इंटरनेट पर बिताए गए समय की सही जानकारी नहीं दी। वर्तमान दौर में सोशल मीडिया से बच्चे और किशोर न सिर्फ तेजी से जुड़ रहे हैं बल्कि इसकी लत के शिकार हो रहें हैं। इसी डिजिटल लत से छुटकारा पाने के लिए अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया व अल्जीरिया सहित कई देशों में क्लीनिक खोले गए हैं। अपने देश के भी बेंगलुरु और दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में इंटरनेट डी-एडिक्शन खोले जा रहे हैं। दरअसल, आज देश ही नहीं, दुनिया भर में इंटरनेट की लत एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इस लत को कम करने के लिए ही दुनियाभर में इंटरनेट डी-एडिक्शन सेंटर्स की जरूरत महसूस की जाने लगी है। इन डी-एडिक्शन सेंटर्स पर जिंदगी को ऑफलाइन बनाने पर काम किया जाता है। डिजिटल लत की वजह से लोग अपनी वास्तविक समस्याओं से अब कट रहे हैं, मौलिक चिंतन और मौलिक सोच कम हो रहा है साथ ही लोगों का सामाजिक दायरा भी कम हो रहा है।

इंटरनेट एडिक्शन एक ऐसी मनोस्थिति है, जब लोग घंटों ऑनलाइन गेम, नेट सर्फिंग या सोशल साइट्स पर समय बिताने लगते हैं और कोई समय-सीमा नहीं रहती। खुद पर नियंत्रण कम होता जाता है। इंटरनेट नहीं मिलता, तो अधीर, बेचैन या अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। यहां तक कि झूठ बोलने, समस्याओं से भागने लगते हैं और जल्द ही नकारात्मक तक हो जाते हैं। असल में युवा वर्ग सूचनाओं के बोझ से दबा जा रहा है और उसके खुद के सोचने और समझनें की क्षमता लगातार कम होती जा रही है साथ ही काम में मौलिकता की आभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मशहूर लेखक निकोलस कार ने मानव मन-मस्तिष्क पर इंटरनेट के प्रभाव विषय पर अपनी एक चर्चित पुस्तक द शैलोज में कहा है, इंटरनेट हमें सनकी बनाता है, हमें तनावग्रस्त करता है, हमें उस ओर ले जाता है जहां हम इस पर ही निर्भर हो जाएं। बिना मोबाइल या फोन के एक पूरा दिन बिताने की कल्पना अब बहुत मुश्किल लगती है, कुछ के लिए तो शायद असंभव! लेकिन हाल में ही पोलैंड वासियों ने डे विदआउट सेल फोन अभियान के तहत अपना पूरा दिन बिना मोबाइल के ही बिताया। वहां लोगों को वास्तविक दुनिया से परिचित कराने और फोन पर संदेशों के आदान-प्रदान की जगह आमने-सामने बैठकर रिश्तेदारों व दोस्तों से बात करने का मौका देने के लिए ही डे विदआउट सेल फोन अभियान चलाया गया।

असल में पोलैंड के ज्यादातर युवा क्लासरूम के साथ-साथ खाना खाते और सिनेमा देखते वक्त भी फोन का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से देश में फोनोलिज्म यानी फोन की लत की बीमारी में इजाफा हुआ है, ऐसें में इस तरह के अभियान की पहल की गई। आज के समय में सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि युवाओं के अलावा कम उम्र के बच्चे भी अब डिजिटल लत के शिकार हो रहे हैं। वैसे तो साइबर एडिक्शन की समस्या पूरी दुनिया में फैली है लेकिन दुनिया में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी वाले भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह समस्या ज्यादा गंभीर है। और अब समय आ गया है कि जब इसका समाधान तलाशा जाए नहीं तो यही मानव संसाधन सबसे ज्यादा दिग्भ्रमित होगा। कुल मिलाकर साइबर एडिक्शन की लत से छुटकारा पाने के लिए सरकार के साथ साथ सामाजिक और परिवार के स्तर पर पहल करनी होगी जिसमें हमें यह प्रण लेना होगा कि छोटे बच्चों को घर और स्कूल में मोबाइल फोन से दूर रखा जाए साथ ही भारत में भी डे विदआउट सेल फोन जैसे अभियान चलाने की जरूरत है।

■ शशांक द्विवेदी
(वरिष्ठ पत्रकार)

ट्विटर

जनता ने हमें जनादेश दिया है और अब बिना समस्या के हम मजबूत और स्थिर सरकार देंगे। विपक्ष जिस तरह का भ्रम फैला रहा था, वह भी दूर हो गया है।

बीएस येदियुरप्पा, मुख्यमंत्री

हम हार स्वीकार करते हैं। 15 सीटों पर मतदाताओं के जनादेश से हमें सहमत होना पड़ेगा, मगर हम सरकार के काम की पोल जनता के सामने खोलते रहेंगे।

एचडी कुमारस्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री

सत्यार्थ

विफलता से डर ठीक नहीं

अमेरिका में एल्कॉट नाम की एक बच्ची अपनी बीमार मां और छोटी बहनों के साथ रहती थी। वह अपनी मां और छोटी बहनों को रोज ही रोटी के लिए संघर्ष करते देखती थी। बीमार मां और बहनों की यह हालत देख एल्कॉट ने पैसा कमाने के लिए लिखना शुरू किया। उसने अपनी कहानियां संपादकों के पास भेजनी शुरू कर दीं। उसकी सभी कहानियां खेद सहित वापस लौट आती थीं। यह देख उसकी बहनें कहतीं- दीदी, लिखने से तुम कभी रोटी नहीं जुटा पाओगी, इससे अच्छा है कि तुम दूसरे कामों में ध्यान लगाओ। एल्कॉट कहती-तुम चिंता मत करो, आरंभ में सभी कामों में विफलता ही मिलती है। लेकिन हिम्मत हारना ठीक नहीं। एल्कॉट आम लड़कियों से अलग थी। वह टॉमबॉय की तरह रहती थी। उसकी कुछेक कहानियां धीरे-धीरे प्रकाशित होने लगीं। एक दिन उसने एक उपन्यास लिखना शुरू किया। उस उपन्यास को नाम दिया 'लिटिल विमिन' और उसके कथानक में भी टॉमबॉय नामक लड़की को ही रचा। उपन्यास पूरा करने के बाद एल्कॉट उसे एक संपादक को दे आई और बोली- अगर आपको ठीक लगे तो इसे छाप देना, नहीं तो वापस कर देना। संपादक ने वह उपन्यास प्रकाशित करने का निर्णय लिया। जब यह उपन्यास बाजार में आया, तो लोगों ने इसे हाथोंहाथ लिया। देखते ही देखते यह बेस्ट-सेलर बन गया। ज्यादातर लड़कियों को 'लिटिल विमिन' का कथानक पसंद आया। इस तरह कुछ ही समय बाद एल्कॉट को धन और यश दोनों ही प्राप्त हो गए। इस प्रकार, एल्कॉट ने अपने जीवट से अपनी छोटी बहनों को बता दिया कि यदि कोई हिम्मत न हारे और मन लगाकर अपना काम करे तो उसे हर हालत में सफलता मिलकर रहेगी।

■ रेनू सैनी

पृष्ठ 1 का शेष

नागरिकता संशोधन बिल: राहुल

नष्ट करने के ''व्यवस्थित एजेंडे'' के खिलाफ लड़ेगी. प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, ''बीती रात लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के साथ भारत कट्टरता एवं संकुचित विचारों वाले अलगाव से भारत के वादे की पुष्टि हुई. हमारे पूर्वजों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण दिये. उस स्वतत्रंता में समता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है।''

उन्होंने कहा, ''हमारा संविधान, हमारी नागरिकता, एक मजबूत एवं एकजुट भारत के हमारे सपने से हम सभी से जुड़े हुए हैं।''

कांग्रेस महासचिव ने कहा, ''हम सरकार के उस एजेंडे के खिलाफ लड़ेंगे जो हमारे संविधान को व्यवस्थित ढंग से खत्म कर रहा है तथा उस बुनियाद को खोखला कर रहा है जिस पर हमारे देश की नींव पड़ी।''

सोमवार रात नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिली. बिल में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है।

एक मिसाल

पेड़ बचाने के लिए पत्थरों से कागज बना रहे हैं दो ऑस्ट्रेलियाई

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के प्रदूषण से लड़ने में पेड़-पौधों की भूमिका को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। मगर क्या पेड़ों के बिना कागज बनाना संभव है? लेकिन ऐसा ही एक असंभव सा दिखने वाला कार्य ऑस्ट्रेलिया के दो उद्यमी केविन गार्सिया और जॉन त्से ने कर दिखाया है। ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी केविन गार्सिया और जॉन त्से की तकनीक कुछ ऐसा ही कर रही है। एक साल तक शोध करने के बाद उन्होंने कागज बनाने का ऐसा विकल्प तैयार किया है, जो बिना पेड़ों की कटाई किए तैयार किया जा सकता है। इससे न सिर्फ जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद मिलेगी बल्कि प्रदूषण भी कम होगा।

खंडहर इमारत का किया इस्तेमाल

ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले दोनों उद्यमी जुलाई 2017 से अपने 'कार्स्ट स्टोन पेपर' स्टार्टअप के जरिए खंडहर पड़ी इमारतों और निर्माणाधीन बिल्डिंग से पत्थरों की छीलन का इस्तेमाल करके यह अनोखा कागज तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तकनीक से उनका मकसद पैसा कमाना नहीं है।

मूल जानकारी होना है जरूरी

दोनों उद्यमी मानते हैं कि किसी भी नए कार्य को करने के लिए उसके बारे में मूल बातें पता होनी चाहिए। वह कहते हैं कि हमें पता था कि शुरुआती तौर पर कागज बनाने के लिए किन-किन मूल तत्वों का होना जरूरी है। उद्यमियों के मुताबिक, जिंदगी में हर एक बात पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए खासतौर पर शिक्षा के स्तर पर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक, 40 फीसदी लकड़ी अकेले कागज उद्योग ही इस्तेमाल करता है।

ऐसे बनाते हैं पेपर

चूना पत्थर इकट्ठे करके उसे बारीक स्टोन डस्ट पाउडर बनाते है। इसमें एचडीपीई (उच्च घनत्व पॉलीइथाइलीन) रेजिन मिलाया जाता है, जो फोटोडिग्रेडेबल होता है। सूर्य के प्रकाश में आने पर यह क्षीण होकर 90 फीसदी कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। इस पेस्ट जैसे मिश्रण को मशीन पर छोटे टुकड़ों में बदलकर गर्म करने के बाद रोलर से कागज शीट बनाई जाती है।

पार्टनर से करनी है शादी की बात?

हमेशा रखें इन 5 बातों का ध्यान

शादी को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। खासतौर पर लंबे समय तक एक रिश्ते में रहने के बाद गर्लफ्रेंड ब्वायफ्रेंड में ये दुविधा रहती है। रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों न चल रहा हो पर जब बात शादी की आती है तो लोग फंसे नजर आते हैं। लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर किस वक्त के बाद शादी के लिए हां करें या पार्टनर से शादी की बात कब करें। अगर आपको भी शादी की बात करनी है तो इन 5 बातों का ध्यान रखें।

▸ जब साथी पर हो जाए पूरा भरोसा

किसी भी रिश्ते की नींव भरोसा होती है। ये जरूरी नहीं कि आप जिससे प्यार करते हों उस पर आंख बंद करके भरोसा भी कर लें। विश्वास एक ऐसी चीज हो जो आपके रिश्ते को जोड़ती है। विश्वास की कमी से रिश्ता टूट भी सकता है। शादी की बात तभी करें जब आपको अपने साथी पर पूरा भरोसा हो जाए।

▸ पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्शन

हर रिश्ते में पैशन होना बहुत जरूरी है वरना जिंदगी बोरिंग लगने लगती है। जितना ज्यादा समय आप एक-दूसरे के साथ बिताते हैं, रिश्ता उतना ही गहरा होता जाता है, पर शादी की बात से पहले ये जरूर टटोल लें कि आपका साथी के साथ इमोशनल कनेक्शन कितना है।

▸ आर्थिक स्थिति का रखें ध्यान

शादी का निर्णय लेने से पहले कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, उनमें से एक है आर्थिक निर्भरता, शादी से पहले और शादी के बाद के खर्चों में जमीन- आसमान का अंतर होता है। शादी का फैसला करते वक्त अपनी और पार्टनर दोनों की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें।

▸ जब झगड़ों को सुलझाना जानते हों

जहां प्यार होता है वहां लड़ना- झगड़ना आम बात है, पर शादी के बारे में तभी सोचें जब आप रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए झगड़ों को सुलझाने में यकीन रखते हों। शादी के बाद के झगड़ों को बहुत धैर्य से सुलझाना पड़ता है।

▸ पार्टनर के परिवार का रखें ध्यान

शादी का निर्णय करते समय सबसे जरूरी और अहम बात है आपके पार्टनर का परिवार कैसा है? समस्या तब हो जाती है जब आप अपने साथी को तो अपनाना चाहते हैं लेकिन उसके परिवार को नहीं, शादी के निर्णय लेते समय साथी के साथ उसके परिवार को भी दिमाग में रखें।

सचिन का रिकॉर्ड तोड़ शेफाली ने रचा इतिहास

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 मैच में शानदार बल्लेबाजी करके टीम को मैच जिताने में अहम योगदान दिया। पहले टी20 मैच में 15 साल की शेफाली अर्धशतक जड़ने वाली भारत की सबसे युवा बल्लेबाज बन चुकी हैं। सचिन तेंदुलकर का शेफाली वर्मा ने 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा ओपनर शेफाली वर्मा ने अपने पांचवें ही टी20 में आतिशी अर्धशतक जमाया। शेफाली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में महज 49 गेंद पर 73 रन की तेज पारी खेली। शेफाली ने 15 साल 285 दिन में टी20 अर्धशतक जड़ इतिहास रच दिया है। इस पारी में शेफाली ने 6 चौके और 4 छक्के लगाए। यह टी20 क्रिकेट में उनका पहला अर्धशतक था। बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 214 दिन में अपना पहला अर्धशतक बनाया था। रोहित शर्मा ने सितंबर 2007 में टी20 क्रिकेट का पहला अर्धशतक बनाया था। इस वक्त रोहित 20 साल के हो चुके थे।

शेफाली दाहिने हाथ की बल्लेबाज हैं और दाहिने हाथ से ही आफ स्पिन गेंदबाजी भी करती हैं। घरेलू क्रिकेट में वे हरियाणा की टीम से खेलती हैं। शेफाली का जन्म 28 जनवरी 2004 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ। इनके पिता का नाम संजीव वर्मा है। संजीव को भी क्रिकेट खेलने का शौक था, लेकिन पर्याप्त समर्थन और परिस्थितियों के अभाव में वे इस खेल में आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन बेटी को उन्होंने क्रिकेट में आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया।

पिता ने ही दी ट्रेनिंग

शुरुआत में शेफाली को ट्रेनिंग उनके पिता ने ही दी। रोहतक में उस समय लड़कियों के लिए क्रिकेट सिखाने वाली कोई बड़ी अकादमी नहीं थी। संजीव वर्मा ने लड़कों को क्रिकेट प्रशिक्षण देने वाली अकादमी में बात की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कुछ समय बाद उनके स्कूल ने लड़कियों को क्रिकेट सिखाने की व्यवस्था शुरू की। जिसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया।

हरियाणा महिला क्रिकेट टीम में हुई थीं शामिल

आगे चलकर शेफाली को हरियाणा की महिला क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया। कड़ी मेहनत और शानदार प्रदर्शन की बदौलत उन्हें भारत के तुमन मिनी आईपीएल यानी कि तुमन्स टी-20 चैलेंज टूर्नामेंट में मिताली राज के नेतृत्व वाली वेलोसिटी टीम में शामिल कर लिया गया। वेलोसिटी की टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में भी पहुंची, लेकिन हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली सुपरनोवा के हाथों हार गई। घरेलू मैचों में अच्छे प्रदर्शन की बदौलत, जल्दी ही शेफाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दरवाजे भी खुल गए। सितंबर 2019 में शेफाली को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ट्वेंटी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया। उन्हें भारतीय टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज के ट्वेंटी-20 क्रिकेट से संन्यास लेने पर टीम में शामिल किया गया।

किया पिता का सपना साकार

24 सितंबर 2019 को उन्होंने अपना पहला ट्वेंटी-20 मैच खेला। इस तरह शेफाली का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रवेश हुआ। इस तरह से, इनके पिता का अपनी बेटी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनाने का सपना साकार हुआ। इस तरह से 15 साल 239 दिन की उम्र में उन्हें अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने का मौका मिला। टी-20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड भी शेफाली के नाम दर्ज हुआ। किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के क्रम में वे दूसरे नंबर पर हैं। इसके पहले गार्गी बनर्जी उनसे कम उम्र में भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि पुरुष क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का रिकार्ड, सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है, जिन्हें 16 साल 238 दिन की उम्र में भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका मिला था।

इन से लें सीख

कभी घी खाने तक के पैसे नहीं थे घर में मेहनत के दम किया सपना पूरा

बजरंग पूनिया ने पुरुषों के 65 किग्रा फ्री स्टाइल वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया ने मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचिर को 8-7 से हराकर तीसरा पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में तीन पदक जीतने वाले वह भारत के पहले पहलवान बन चुके हैं। बजरंग ने इससे पहले 2013 में कांस्य और 2018 में रजत पदक जीता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब बजरंग पूनिया के पास घी खाने तक के लिए रुपए नहीं थे। बजरंग पूनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 को हरियाणा के झज्जर गांव में हुआ था। बजरंग पूनिया को कुश्ती विरासत में मिली है क्योंकि उनके पिता बलवान पूनिया अपने समय के नामी पहलवान रहे हैं। लेकिन गरीबी ने उनके करियर को पंख लगने नहीं दिए। कुछ ऐसा ही बजरंग के साथ भी हो रहा था। बजरंग के पिता के पास अपने बेटे को घी खिलाने तक के पैसे नहीं होते थे। रुपये बचाने के लिए उन्होंने बस की जगह साइकिल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का निर्णय लिया। ऐसा करके जो रुपये बचते, उसे वह अपने बेटे के खाने पर खर्च करते थे। ऐसे हालातों से गुजरते हुए बजरंग ने पहलवानी की दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। बजरंग पूनिया की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी हुई। इसके बाद सात साल की उम्र में कुश्ती शुरू की और उन्हें उनके पिता द्वारा बहुत सहयोग मिला, जिसके बाद बजरंग ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपना स्नातक भी पूरा किया है।

2013 में बुडापेस्ट में जीता था कांस्य पदक : बजरंग पूनिया ने साल 2013 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप दिल्ली में भाग लिया था, जिसमें वह सेमीफाइनल तक का सफर तय कर पाए थे। इसके बाद बजरंग पूनिया ने 2013 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप बुडापेस्ट, हंगरी में 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। एक साल बाद वर्ष 2014 में उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में 61 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। साल 2014 में ही एशियाई खेल इनचियन, दक्षिण कोरिया में फिर से रजत पदक अपने नाम किया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2017, दिल्ली में बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके बाद 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया और 2018 के ही एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक से देश का नाम रोशन किया।

34 किमी दूर जाते थे : बजरंग के पिता बताते हैं कि साल 2005 में गांव में हमारा डेढ़ एकड़ का खेत था। उस समय बजरंग अखाड़े में जाता था। 2005 में हमने उसे छारा गांव के लाला दीवानचंद अखाड़े में दाखिल करा दिया था। ये हमारे घर से 35 किमी दूर था। बजरंग का दिन सुबह तीन बजे शुरू होता था और आज भी उसकी यही आदत है। बजरंग पूनिया ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती के गुर सीखे और अब वह देश का मान बड़ा रहे हैं। हरियाणा के रहने वाले बजरंग पूनिया ने 2014 में कॉमनवेल्थ खेलों में 61 किलोग्राम वर्ग में रजत जीता था।

हालात बदलने के लिए खेली कुश्ती : बजरंग पूनिया बताते हैं कि बचपन में ऐसी हालत थी कि जब वह पहलवानी का अभ्यास करके घर लौटते थे, तो रोज रात एक जैसा खाना ही खाते थे क्योंकि उन्हें पता होता था कि घर जाकर क्या मिलना है। बजरंग पूनिया और उनका परिवार दूध-रोटी पर गुजारा कर रहा था। यह सब देखकर उन्हें दुख भी होता था लेकिन वह अपने हालातों के आगे मजबूर थे और उनको बदलना चाहते थे। बजरंग पूनिया को लगता था कि इस जिंदगी को कुश्ती के बूते ही बदला जा सकता है। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान कुश्ती की तरफ लगाया और अपने गुरु से हर एक बारीकी को बेहतर तरीके से सीखा।

पढ़ाई के जज्बे ने जयकुमार वैद्य को दिलाया खास मुकाम

मुंबई के कुर्ला स्लम में रहने वाले जयकुमार वैद्य का पूरा बचपन महरूमियों और तकलीफों के बीच बीता। वह अपनी मां नलिनी वैद्य की गोद में ही थे, तभी मां और उन्हें घर से निकाल दिया गया और कुछ दिनों बाद पिता ने मां को तलाक का नोटिस भी थमा दिया। मगर मां जिंदगी से मायूस नहीं हुईं और बेटे की अच्छी परवरिश को अपने जीने का मकसद बना लिया।

एक पैकेजिंग कंपनी में जय की मां ने क्लर्क की नौकरी कर ली, ताकि घर चला सके। मगर किस्मत ने उन्हें फिर धोखा दिया और 2003 में नानी की बीमारी के कारण जय की मां को नौकरी छोड़नी पड़ी। वे बड़े मुश्किल भरे दिन थे। गैस ज्यादा न खर्च हो पाए, इसके लिए मां तीन-तीन दिनों की रोटियां एक साथ बना लिया करती थीं। ऐसे समय में स्थानीय मंदिर ट्रस्ट ने इनकी मदद की। बेटा कम से कम 12वीं पास कर जाए, इसके लिए मां ने कई गैर-सरकारी संस्थाओं और ट्रस्टों से संपर्क साधा, मगर कई बार मदद की बजाय नसीहतें मिलतीं कि कहां उसे पढ़ाने-लिखाने में लगी हो, ड्राइवर बनाओ। जय बचपन से ही पढ़ने में बहुत जहीन थे। स्कूल में हमेशा आगे रहते, इसलिए मां का मन ऐसी बातें सुन तड़प उठता था, डिस्कवरी चैनल और स्पेस मूवी देखकर विज्ञान के प्रति उनकी दिलचस्पी जगी। मां की बेबसी और बेचैनी देख जय हमेशा दुखी रहते थे। महज 11 साल की उम्र में उन्होंने एक टीवी मरम्मत करने वाली दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। वहां से उन्हें महीने के 4,000 रुपए मिल जाते थे। जय ने कपड़े की दुकान पर भी काम किया और अपने इलाके के बच्चों के असाइनमेंट भी किए, ताकि मां का बोझ कुछ हल्का कर सके। इतने भीषण संघर्ष में भी आगे पड़ने के

अपने जज्बे को उन्होंने कभी कमजोर नहीं पढ़ने दिया और वह इस मामले में खुशकिस्मत थे कि बदहाली के बावजूद मां ने हमेशा उनका साथ दिया। जय की मेहनत रंग लाई और उन्हें मुंबई में केजे सोमैया इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया।

मां-बेटे की जिंदगी की एक बड़ी साध पूरी हो गई। सुखद बात यह भी थी कि जय को स्कॉलरशिप मिल गई। और फिर मेस्को ट्रस्ट ने ब्याज मुक्त कर्ज मुहैया कराने में उनकी मदद कर दी, जिससे फीस की बाकी रकम चुकाने में आसानी हो गई। उन्होंने खूब मेहनत की और उनकी प्रतिभा को सम्मान भी मिला। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही जय को रोबोटिक्स के क्षेत्र में तीन राष्ट्रीय और चार राज्य स्तरीय पुरस्कारों से नवाजा गया। इंजीनियरिंग करने के बाद उन्हें प्रतिष्ठित शोध संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर) में बतौर रिसर्चर काम करने का मौका मिला। उन्हें 30,000 रुपए का मासिक वजीफा मिलता था। जय कहते हैं, हम दोनों के लिए यह काफी बड़ी रकम थी। हमने सबसे पहले खस्ताहाल कमरे की मरम्मत कराई। उन्होंने अमेरिका से मास्टर्स डिग्री के लिए जीआरई, टीओईएफएल परीक्षाओं के वास्ते पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। इसके लिए अच्छी-खासी रकम चाहिए थी।

इस बीच उनके दो पेपर अंतरराष्ट्रीय साइंस जर्नल में भी प्रकाशित हो चुके थे। उन्होंने विदेशी लड़कों को ऑनलाइन कोचिंग देनी शुरू कर दी। साल 2017 में लंदन के प्रतिष्ठित इंपीरियल कॉलेज से उन्हें पहला ऑनलाइन छात्र मिला। बाद में छात्रों की संख्या बढ़ती गई। कोचिंग से हासिल पैसे से जय ने अपने सारे कर्ज चुका दिए। मजबूत इच्छाशक्ति की बदौलत जय ने हर उस मुकाम को हासिल किया, जिसे उन्होंने कभी चाहा था। अमेरिका की मशहूर वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें पीएचडी का प्रस्ताव दिया। साथ ही, सालाना करीब 24,000 डॉलर (माह के एक लाख, 40 हजार रुपए से भी अधिक) की स्कॉलरशिप की सुविधा दी गई। कभी 10 रुपए के लिए तरसने वाला बालक आज हिन्दुस्तान के गुदड़ी के लालों के लिए एक नजीर बन गया है। नोबेल विजेता जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, खुद को पा लेने का नाम जीवन नहीं, अपने आप को गढ़ना ही जिंदगी है। जयकुमार वैद्य ने इस कथन को चरितार्थ किया है।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor: ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.

नोटबंदी के बाद मुद्रा की मात्रा बढ़ी और जाली मुद्रा पर रोक लगी: सरकार

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

सरकार ने नोटबंदी को देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी फैसला करार देते हुए मंगलवार को कहा कि इससे न सिर्फ मुद्रा की मात्रा बढ़ी है बल्कि जाली मुद्रा पर भी रोक लगी है। साथ ही डिजिटल भुगतान में इजाफे से नोटों के परिचालन को कम करने में सफलता मिली है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान नोटबंदी के फैसले के प्रभाव से जुड़े एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार ने आठ नवंबर 2016 को पांच कारणों से 1000 और 500 रुपये के नोट के वैध मुद्रास्वरूप को समाप्त करने का निर्णय लिया था। सपा के विशंभर प्रसाद निषाद द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में ठाकुर ने कहा कि

कालेधन को खत्म करने, जाली नोट की समस्या से निपटने, आतंकवाद के वित्तपोषण की जड़ पर प्रहार करने, गैर औपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने और भारत को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिये डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया था। इस फैसले से अर्थव्यवस्था में नोटों की कमी आने से जुड़े पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि चार नवंबर 2016 को 17741.87 अरब रुपये के नोट प्रचलन में थे, इसकी मात्रा दो दिसंबर 2019 को बढ़कर 22356.48 अरब रुपये हो गयी। ठाकुर ने कहा कि नोटबंदी और इसके बाद डिजिटलीकरण तथा अनौपारिक अर्थव्यवस्था में नकदी के प्रयोग की कमी से 3046.05 अरब रुपये के नोटों के परिचालन को कम करने में सफलता मिली है। नोटबंदी के बाद जाली नोटों में कमी आने के बारे में उन्होंने बताया कि आरबीआई ने सूचित किया है कि बैंकिंग प्रणाली में 2016-17 के दौरान 7.62 लाख नोट, 2017-18 में 5.22 लाख और 2018-19 में 3.17 लाख जाली नोटों की पहचान की गयी थी। अत- नोटबंदी के बाद जाली मुद्रा पर रोक लगी है।

आतंकवाद के खिलाफ नोटबंदी के सकारात्मक प्रभाव के बारे में ठाकुर ने बताया कि 1000 और 500 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद आतंकवादियों के पास पड़ी अधिकतर नकदी बेकार हो गयी। ठाकुर ने कालेधन के खिलाफ अभियान में मिली कामयाबी का जिक्र करते हुये कहा कि नवंबर 2016 से मार्च 2017 के दौरान आयकर विभाग की 900 टीमों ने तलाशी और जब्ती की कार्रवाई कर 636 करोड़ रुपये की नकदी और 7961 करोड़ रुपये की अघोषित आय की स्वीकृति सहित 900 करोड़ रुपये की जब्ती की। नोटबंदी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन में मूडीज रेटिंग के मुताबिक गिरावट आने के पूरक प्रश्न के उत्तर में ठाकुर ने कहा कि मूडीज ने 2016 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की रेटिंग कम नहीं की है। साथ ही नोटबंदी के बाद आयकर दाताओं की संख्या 6.14 करोड़ से बढ़कर 8.14 करोड़ हो गयी है। इसके अतिरिक्त डिजिटल भुगतान से लेनदेन की मात्रा 51 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2017-18 में 2071 करोड़ बढ़कर 2018-19 में 3134 करोड़ हो गयी है।

कुलदीप सिंह सेंगर को सजा होगी या नहीं, 16 दिसंबर को आएगा फैसला

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

चर्चित उन्नाव केस पर दिल्ली की अदालत 16 दिसंबर को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अगस्त महीने में ही आरोप तय किए थे।

चर्चित उन्नाव केस पर दिल्ली की एक अदालत ने आज फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मुख्य आरोपी हैं। अदालत 16 दिसंबर को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि उन्नाव रेप केस के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर

फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अगस्त महीने में ही आरोप तय किए थे। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोप तय किए। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (बलात्कार) और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।

विवादित CAB के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर में प्रदर्शन

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक पार्टियों, छात्र संगठनों और नागरिक संस्थाओं ने विवादित नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ मंगलवार को प्रदर्शन किया। 'नार्थईस्ट स्टूडेंट्स यूनियन' (एनईएसओ)ने विधेयक के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों और संगठनों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। माकपा की दिल्ली समिति के सदस्य भी यहां विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इससे पूर्व माकपा के सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया था। वाम दल के सदस्य यहां हाथों में तख्तियां लिए दिखें, जिस पर लिखा

था ''कैब वापस लो'' और ''धर्म आधारित कैब नहीं चलेगा''।

माकपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश करात ने कहा,''नागरिकता संशोधन विधेयक सोमवार की रात लोकसभा में पारित हो गया। यह कानून संविधान के खिलाफ है। विरोध के बावजूद यह विधेयक संसद में पारित हो जाएगा। पहली बार, धर्म नागरिकता के लिए आधार बना है।'' कई नागरिक संस्थाएं भी आज शाम नागरिकता संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी।

पंजाब के मुख्य सचिव द्वारा जनगणना 2021 की तैयारियों का जायजा

राज्य में जनगणना का पहला चरण 15 मई से 29 जून, 2020 तक होगा

■ चंडीगढ़/न्यूज नेटवर्क

पंजाब के मुख्य सचिव करण अवतार सिंह ने मंगलवार को यहाँ रा%य स्तरीय कोर्डीनेशन कमेटी में जनगणना-2021 की तैयारियों का जायज़ा लिया। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जनगणना दो चरणों में की जायेगी। पहले चरण अधीन 15 मई से 29 जून, 2020 तक घरों की गणना करने के साथ-साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अपडेट किया जायेगा। दूसरे चरण में 9 से 28फरवरी, 2021 तक जनगणना की जायेगी और 1 से 5 मार्च 2021 तक सुधार किया जायेगा।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि प्रशासनिक इकाईयों की सीमाएं 31 दिसंबर, 2019 के बाद बढ़ाई नहीं जा सकेंगी। इससे रा%य में जनगणना 2021 मुकम्मल होने तक मौजूदा नगर पालिकाओं, गाँवों, तहसीलों, विकास ब्लॉकों, सब डिवीजनों, ज़िलों आदि की सीमाओं में कोई भी बदलाव करने पर पाबंदी होगी। मुख्य सचिव को अवगत करवाया गया कि मास्टर ट्रेनरों को मैगसीपा, चंडीगढ़ में 16से 21 दिसंबर, 2019 तक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

जनगणना 2021 के फील्ड के कार्य के लिए जनगणना करने वालों और सुपरवाईज़रों जिनमें राज्य सरकार के अधिकारी, क्लर्क और अध्यापक, स्थानीय अथॉरिटी आदि शामिल हैं, की ड्यूटी लगाई जायेगी। उनको इस सम्बन्धी 4 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। जनगणना की प्रक्रिया को द्विभाषीय मोबाइल ऐप

और पेपर फॉर्मेट की सहायता से पूरा किया जायेगा। घरों की सूची तैयार करने के समय मैप/जीओ-रैफरैंसिंग का प्रयोग करना भी विचाराधीन है।

मुख्य सचिव ने जनगणना 2021 की रूप रेखा सम्बन्धी विचार-विमर्श किया और डिज़ाइन और तकनीकों में सुधार करने पर ज़ोर दिया गया जिससे जनगणना के अमल को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।

इस मीटिंग के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के वित्त कमिश्नर सीमा जैन, स्थानीय निकायों के प्रमुख सचिव ए. वेनू प्रसाद, सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुमार, विशेष सचिव योजना डी.एस. मांगट और अतिरिक्त सचिव राजस्व कैप्टन करनैल सिंह भी उपस्थित थे।

डायरैक्टर जनगणना पंजाब और चंडीगढ़ डा. अभिषेक जैन ने अग्रिम मुकम्मल की जाने वाली गतिविधियों बारे जानकारी दी। मीटिंग में ज्वाइंट डायरैक्टर मृत्युंजय कुमार और जनगणना विभाग के अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया।

कांग्रेस विधायक ने इनवेस्टर्स मीट में घोटाले का मुद्दा उठाया

सीएम ने भाषा का ध्यान रखने की दी सलाह

■ धर्मशाला/न्यूज नेटवर्क

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को कांग्रेस सदस्यों ने नवंबर में हुए राइजिंग ग्लोबल इनवेस्टर्स मीट में कथित घोटाले को लेकर व्यवधान पैदा किया। विधानसभा की कार्यवाही यहां तपोवन में शुरू होते ही शीतकालीन सत्र के लगातार दूसरे दिन यह मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस के सदस्य अध्यक्ष के आसन के समीप पहुंचे गये और नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस के मुकेश अग्निहोत्री ने इसे राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस विधायकों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा को पंजाब और बिहार की

विधानसभाओं की तरह नहीं बनाना चाहिए।उन्होंने अपील की कि कांग्रेस सदस्य कोई भी मुद्दा उठाते समय अपनी भाषा का ध्यान रखें।

मंदिर निर्माण से अयोध्या में पर्यटन बढ़ने के बारे में सरकार मंत्री ने कुछ भी कहने से किया इनकार

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद पर्यटन बढ़ने के सवाल पर मंगलवार को संसद में कुछ भी कहने से यह कहकर इनकार कर दिया कि इस बारे में कोई ''अध्ययन एवं आंकड़े''नहीं हैं। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उनसे यह पूछा गया था कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से पर्यटन में क्या कई गुना वृद्धि हो सकती है? पटेल ने कहा, ''इस संबंध में किसी अध्ययन एवं आंकड़ों के अभाव में कुछ नहीं

कहा जा सकता।''उल्लेखनीय है कि राम जन्मभूमि स्वामित्व मुद्दे पर दशकों तक चले विवाद का पटाक्षेप करते हुए उच्चतम न्यायालय ने नौ नवंबर को अपना निर्णय सुनाया था जिससे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रश्स्त हो गया।पटेल ने बताया, ''वर्ष 2017-18 में 133.31 करोड़ रूपये की लागत से स्वदेश दर्शन योजना के रामायण परिपथ विषय के अंतर्गत अयोध्या का विकास'' स्वीकृत किया गया था। ताजा जानकारी के अनुसार संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस परियोजना के लिए 99.21 करोड़ रूपये की राशि जारी की गयी है।

धर्मसोत द्वारा स्वै-रोज़गार के लिए कर्ज प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर

एस.सी. और बी.सी. कॉर्पोरेशन के साथ की समीक्षा मीटिंग

■ चंडीगढ़/न्यूज नेटवर्क

पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री स. साधु सिंह धर्मसोत ने राज्य के पिछड़ी श्रेणियों, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति वर्ग से सम्बन्धित नौजवानों को स्वै-रोज़गार के लिए दिए जाते कर्ज़ की प्रक्रिया को आसान बनाने पर ज़ोर दिया है। आज यहाँ एस.सी. और बी.सी. कॉर्पोरेशनों के उच्च अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा मीटिंग के दौरान स. धर्मसोत ने कहा कि पिछड़ी श्रेणियों, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति वर्ग से सम्बन्धित नौजवानों को स्व-रोज़गार शुरू करने के लिए निर्धारित समय सीमा में कर्ज देने के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अब जिला स्तर पर जिला कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में बनी समिति को 1 लाख रूपए तक के अलग-अलग कर्जों को पास करने का अधिकार दिया जायेगा और जल्द ही इस सम्बन्धी विभागीय आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को उन कर्जदारों के कर्जे माफ करने सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार करने के लिए भी कहा, जिनकी मौत हो चुकी है।

स. धर्मसोत ने राज्य के नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि वह स्व-रोज़गार शुरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कर्ज कल्याण स्कीमों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। वर्णनयोग्य है कि बैकफिंको और एस.सी. कॉर्पोरेशन द्वारा डायरेक्ट लोन स्कीम के अंतर्गत 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर 50 हज़ार से 1 लाख रूपए तक का कर्ज़ मुहैया करवाया जाता है। यह कर्ज़ डेयरी फार्मिंग (3-5 पशु), पोल्ट्री फार्मिंग, सब्जियां उगाना, मधुमक्खी पालन के लिए, कारपैंटरी /फर्नीचर /लौहार का काम, आटा चक्की /कोहलू, ऑटो रिक्शा (पैसंजर /ढुलाई), जनरल स्टोर (किराना / केटल /पोल्ट्री फीड), हार्डवेयर स्टोर (सैनिटरी और बिल्डिंग मैटीरियल, लोहा आदि), कपड़ा /रेडिमेड गारमैंट शॉप, किताबें /स्टेशनरी की दुकान, फोटो स्टेट मशीन, टेलरिंग, कृषि के यंत्रों के लिए (फेब्रिकेशन), ऑटो मोबाइल रिपेयर /स्पेयर पार्टस शॉप, ईलेक्ट्रोनिक्स /इलैक्ट्रिकल सेल और रिपेयर, फेब्रिकेशन यूनिट, फोटोग्राफी और वीडीयोग्राफी, हौज़री यूनिट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट (कोई भी सामान बनाने का कारोबार), स्वीट शॉप /ढाबा, ब्यूटी पार्लर और पंडाल या शामियाना सर्विस आदि पेशे शुरू करने के लिए लिए जा सकते हैं। बैकफिंको और एस.सी. कॉर्पोरेशन से कर्ज़ लेने के लिए निर्धारित योग्यताएं पूरा करना जरूरी हैं।

निर्भया गैंगरेप के आरोपी पवन को तिहाड़ जेल में किया गया शिफ्ट

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

निर्भया गैंगरेप के चार दोषियों में से एक पवन को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है। वह मंडोली जेल में बंद था। बाकी के तीन दोषी पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं।

2012 में हुए निर्भया कांड के चार दोषियों को कोर्ट ने पहले ही फांसी की सज़ा सुना दी है। ऊपरी कोर्ट ने भी इनकी सजा को बरकरार रखा है। मामले के दोषियों में से एक, अक्षय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष समीक्षा याचिका दायर की है।

मामले में ट्रायल कोर्ट ने अक्षय को मौत की सजा सुनाई थी। उसकी सजा को दिल्ली उच्च न्यायालय और

उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा। इससे पहले गृह मंत्रालय ने 2012 के सामूहिक बलात्कार के दोषी विनय शर्मा की दया याचिका की फाइल राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को भेज दी है। हालांकि विनय ने राष्ट्रपति के सामने दायर की गई दया याचिका को वापस करने के लिए अपील की थी।

13 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई को होनी है।

डिप्टी कमिशनर ने समाज को शूरवीर सैनिकों के परिवारों के कल्याण हेतु आगे आने किया आह्वाहन

हथियारबन्द झंडा दिवस के अवसर पर 22 लाभपात्रियों को 4 लाख रुपए से अधिक की सहायता के चैक वितरित

■ जालंधर/नीरज शर्मा

डिप्टी कमिशनर जालंधर श्री वरिन्दर कुमार शर्मा ने समाज के हर वर्ग के लोगों को न्योता दिया है कि वह देश की खातिर बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों के परिवारों के कल्याण हेतु आगे आयें क्योंकिउनकी तरफ से दिये बलिदानों के कारण ही आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज यहाँ जिला सुरक्षा सेवाओं कल्याण कार्यालय में हथियारबंद झंडा दिवस के अवसर पर संबोधन करते हुए डिप्टी कमिशनर ने कहा कि हमें देश के शहीदों के बलिदानों पर गर्व होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अलग-अलग हथियारबंद सेनाओं, अर्ध सैनिक बलों के जवान देश की रक्षा के लिए सीमा क्षेत्रों, जंगलों, बर्फीले तूफानों वाले क्षेत्रों और रेगिस्तान में भी पूरी लगन से ड्यूटी निभा रहे हैं, जिस कारण पूरा देश बाहरी हमलों से पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने लोगों को न्योता दिया कि वहफ्लैग डेय के अवसर पर अधिक से अधिक दान करें जिससे सैनिकों

और उनके परिवारों के कल्याण में अपना योगदान पाया जा सके। इस अवसर पर समागम की शुरुआत शहीद शैनिकों को दो मिनट का मौन धारन करके की गई और टोकन फ्लैग लगाने की रस्म कार्यालय डिप्टी कमिशनर में डिप्टी कमिशनर जालन्धर के कालर पर फ्लैग लगा कर की गई। मेजर यशपाल सिंह जिला सुरक्षा सेवाओं कल्याण अधिकारी ने फ्लैग डेय के इतिहास के बारे में जानकारी दी और बताया कि आज़ादी से पहले यह दिन पोपी डेय के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर शहीदों की याद को ताज़ा करने के लिए छोटे -छोटे पेपरों की स्लिपें काटकर आम लोगों में बाँटीं जातीं थीं, जिसके बदले लोग दान देते थे जोकि शहीदों के परिवारों, अपंग सैनिकों के कल्याण हेतु उपयोग की जाती थी। इस अवसर पर 22 लाभपात्रियों को 4 लाख 16 हज़ार रुपए के चैक भी वितरित किये गए। इस अवसर पर जिला सुरक्षा सेवा विभाग का स्टाफ, सेवा मुक्त अधिकारी और समाज की मशहूर शख्सीयतें उपस्थित थे।

नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ पूर्वोत्तर में विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर आगजनी

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ छात्र संगठनों की तरफ से संयुक्त रूप से बुलाया गया 11 घंटे का बंद मंगलवार सुबह पांच बजे शुरू हो गया। पूर्वोत्तर छात्र संगठन (एनईएसओ) ने इस विधेयक के खिलाफ शाम चार बजे तक बंद का आह्वान किया है। कई अन्य संगठनों और राजनीतिक दलों ने भी इसे अपना समर्थन दिया है।

इस बंद के आह्वान के मद्देनजर असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नगालैंड में चल रहे हॉर्नबिल महोत्सव की वजह से राज्य को बंद के दायरे से बाहर रखा गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के मूल निवासियों को डर है कि इन लोगों के प्रवेश से उनकी पहचान और आजीविका खतरे में पड़ सकती है।